

असाधारण TEXTRAORDINARY

NITI I-Wes 1
PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाश्चिस PUBLISHED BY AUTHORITY

ਚ. 100] No. 100] नई फिली, शुक्रवार, मई 26, 1989/ज्येष्ठ 5, 1911

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1989/JYAISTHA 5, 1911

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ तंख्या वी बाली ही विकल्त कि यह अलग संकल्प के रूप में रका जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रासय

(राजस्य विभाग)

स करण

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

फा. म 22/1/89—िंब. क. :—िंबकी कर और वित्त नंद्रालय में सम्बन्धित प्रत्य मामलों के सम्बन्ध में बिचार-विमर्श करने के लिए और 10 फरवरी, 1989 को निर्ध विल्लों में हुए नुष्य मंत्रियों है सम्मेलन में एक संग्रह्म पारित किया गया या जिममें माल के अन्तर-राज्य परेषण पर कर नगाने तथा उससे सम्बन्धिन विभिन्न तरीकों और कुछ मुख्य मंत्रियों की एक समिति द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त के लेयार किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का माय-ताय विए, जाने वाली छूट प्रवान करने की शक्तियों के सम्बन्ध में कन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में भी तिकारित की गई।

क्र इस संकल्प के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने मुखा हो। की एक समिति नियुक्त करने का फैमला किया है जिसका गठन इस प्रकार से होगा:----

 श्री नारायण वल निकारी, मुख्य नंत्री, उत्तर प्रदेश अ**ञ्यक्त**

ः श्री शरद पवार,

मदस्य

नुष्य मंत्री, महाराष्ट्र

-- यही---

3 श्री एम. करणानिधि, नुष्य मंत्री, तमिलमाड्

—वही**∽**-

 श्री ज्योति वसु, मुख्य नंत्री, पश्चिम बंगःल

वही

 श्री मोती लाल बोरा, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश

श्री शिव चरण माथ्र,

- **-**वङ्गी----

मुख्य मंत्री, राजस्थान श्री के. जे. रेड्डी, (भपर संविद, विता मंत्रालय, राजस्व विचान।

माचिव क **रूप** में कार्य **करी**

Member

- 3. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :---
- (1) केला और राज्यों के साय-साथ दिए जाने वाले छूट सम्बन्धी मक्तियों के बारे में मार्गवर्शी सिद्धान्त तैयार करना,
- (2) उनसे सम्बन्धित किसी भ्रन्य बातों के बारे में सिकारिशें करना।
- 4. यह समिति घपने कार्य निब्दादन के बारे में घपनी ही प्रक्रिया तैयार करेती और घपने मध्ययन के प्रयोजन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों में यथाक्यक मुखना मंगायेंगी।
- 5. यह समिति भवनो रियोर्ट 31 जुलाई, 1989 तक प्रस्तुन करेगी।

के. जे. रेड्डी, भार सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) RESOLUTION

New Delhi, the 26th May, 1989

F.No. 22/1/89-ST.—The Chief Minister's Conference held at New Delhi on 9th and 10th February, 1989 to discuss Sales Tax and other matters relating to the Ministry of Finance had adopted a resolution recommending levy of tax on inter-State consignment of goods and various modalities connected thereto and also to the issue of guide lines by the Central Government with regard to the power of exemption to be concurrently vested with the Central Government and the State Governments, after these guidelines are formulated by a Committee of some Chief Ministers.

- 2. In pursuance of this Resolution, the Central Government has decided to appoint a Committee of Chief Ministers with the following composition:—
 - 1. Shri Narayan Datt Tiwari, Chief Minister of Uttar Pradesh

Chairman

Chief Minister of Maharashtra

3. Shri M. Karunanidhi.

2. Shri Sharad Pawar,

- Chief Minister of Tamil Nadu Member
- 4. Shri Jyoti Basu.
 Chief Minister of West Bengal Member
- Shri Moti Lal Vora,
 Chief Minister of Madhya Pradesh
 Member
- Shri Shiv Charan Mathur,
 Chief Minister of Rajasthan
 Shri K.J. Reddy, Additional Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Revenue will function as Secretary to the Committee.
- 3. The terms of reference of the Committee are as under :-
- (i) to formulate guldelines in regard to the power of exemptions to be concurrently vested with the Centre and the States;
- (ii) to make recommendations regarding any other related matters thereto.
- 4. The Committee will evolve its own procedure for its work and may, for the purpose of its study, call for such information as may be necessary from the Central and State Governments.
- 5. The Committee will submit its report by the 31st July, 1989.

K.J. REDDY, Addl. Secy.